



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 240]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 17, 1984/वैशाख 27, 1906

No. 240]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 17, 1984/VAISAKHA 27, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 1984

का० आ० 389(अ):—कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाना चाहती है, उस धारा की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है। इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उक्त अधिसूचना वाला राजपत्र जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिन की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा।

ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

ऐसे आक्षेप या सुझाव, सचिव, उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 के पते पर भेजे जाने चाहिए।

प्रारूप नियम:

1. संक्षिप्त नाम:—इन नियमों का संक्षिप्त नाम मोटरगाड़ी उपकरण नियम, 1984 है।

2. परिभाषाएं:—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) "अधिनियम" से उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) अभिप्रेत है;

(ख) "उपकरण" से अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारी उद्योग विभाग की अधिसूचना सं० का० आ० 932 (अ) तारीख 28-12-1983 के निर्बंधों के अनुसार तद्विहित और संगृहीत उपकरण अभिप्रेत है;

(ग) "कलक्टर" से केंद्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर अभिप्रेत है और इसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपर कलक्टर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क उपकलक्टर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहायक कलक्टर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक सम्मिलित हैं;

(घ) "विकास परिषद" से अधिनियम की धारा 6 के अधीन स्थापित मोटर गाड़ी और महबूज उद्योग विकास परिषद अभिप्रेत है;

(ङ) "मोटर गाड़ी" से अभिप्रेत है मोटरकार, बसें, ट्रक, जीप प्रकार के यान, वैन, स्कूटर, मोटर साईकिल, मोपेड और सभी अन्य मोटर गाड़ियां जो अधिनियम की पहली अनुसूची के उपशीर्षक (5) के अन्तर्गत आती हैं;

(क) उन शब्दों और पदों के, जिनका हममें प्रयोग किया गया है और जिनकी परिभाषा नहीं दी गई है, किन्तु जिनकी परिभाषा केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) या उसके अधीन बनाए गए नियमों में दी गई है, वही अर्थ होंगे जो उनके क्रमशः उक्त अधिनियम या नियमों में हैं।

3. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों का लागू होता—इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और उसके अधीन बनाए गए नियमों, जिनमें वे भी सम्मिलित हैं जो शुल्क के प्रतिवाय से संबंधित हैं, उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में वहां तक लागू होंगे जहां तक वे उक्त अधिनियम और नियमों के अधीन मोटर गाड़ियों के विनिर्माण पर उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं।

4. विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना:—(1) प्रत्येक विनिर्माता, कलक्टर और विकास परिषद के समक्ष प्रत्येक मास की दस तारीख को या उसके पूर्व, पूर्ववर्ती मास के दौरान अपने उपक्रम में विनिर्मित या उत्पादित और वहां से हटाए गए मोटर गाड़ियों की मधों के मधी स्टॉक की विवरणी, इन नियमों के उपाबंध में विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि कोई विनिर्माता उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है या ऐसी विवरणी प्रस्तुत करता है जिसके बारे में कलक्टर या विकास परिषद को यह विश्वास करने का कारण हो कि वह ठीक नहीं है या त्रुटिपूर्ण है तो कलक्टर, विनिर्माता से उसके द्वारा विनिर्मित या उत्पादित मोटर गाड़ियों से संबंधित मधी या किन्हीं लेखाओं को प्रस्तुत करने की उससे अपेक्षा करने हुए सूचना तामील कर सकेगा।

5. उपकर के आगम:—उपकर के आगम प्रथमतः “038—केंद्रीय उत्पाद शुल्क—वस्तु मोटरगाड़ियों पर उपकर” शीर्ष के अधीनधारण की संज्ञित

विधि में जमा किया जाएगा, और केंद्रीय सरकार, इस निमित्त संसद द्वारा विधि द्वारा सम्यक विनियोग किए जाने के पश्चात्, विकास आयुक्त को उतनी राशि दे सकेगा जो वह आवश्यक समझे।

6. खाता खोलना:—उपनियम 5 के अधीन विकास परिषद द्वारा प्राप्त रकम, भारतीय स्टेट बैंक के खाते में रखी जाएगी।

7. विकास परिषद के लेखे:—(1) विकास परिषद, नियम 5 के अधीन अपने द्वारा प्राप्त रकम से संबंधित उचित लेखा बनाए रखेगा।

(2) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लेखाओं का संपरीक्षित विवरण और उसके संबंध में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।

8. विकास परिषद का बजट प्राक्कलन :

(1) विकास परिषद, प्रत्येक वर्ष आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट तैयार करेगा और उसे मंजूरी के लिए केंद्रीय सरकार को उस तारीख को या उससे पूर्व प्रस्तुत करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) जब तक केंद्रीय सरकार बजट को मंजूरी नहीं दे लेती है तब तक कोई भी व्यय उपागत नहीं किया जाएगा।

(3) बजट ऐसे अनुवेशों के अनुसार तैयार किया जाएगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं।

9. विहित प्रशासनिक व्यय:—विकास परिषद, नियम 5 के अधीन अपने द्वारा प्राप्त रकम के वो प्रतिशत से अनधिक राशि का उपयोग, कार्यालय स्थापन और उपकरण, लेखन सामग्री, डाक महसूल, टेलीफोन, तार, टेलीग्राम, सचिवालय में नियोजित कर्मचारी, रिटर्न की मजदूरी और भत्तों, सब्सिडियों के यात्रा और दैनिक मधे व्यय, और परिषद के अधिवेशन करने से संबंधित व्यय पूरा करने के लिए कर सकेगा।

उपाबंध

(नियम 5 देखिए)

मोटर गाड़ी उपकर नियम, 1984 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली मासिक विवरणी का रचना

..... का समाप्त होने वाला मास

कारखाने का नाम

पता

उपकर के अधीन रहने हुए माल का आवि बतियोग		उपकर के अधीन रहने हुए विनिर्मित माल		उपकर के अधीन हटाए गए माल	
वर्णन	मात्रा	वर्णन	मात्रा	वर्णन	मात्रा
1	2	3	4	5	6
अस्त अतिशेष			टिप्पणी		
वर्णन	मात्रा				
7	8	9			

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने ऊपर दशित विनिर्दिष्टियों का अपने/हमारे कारखाने के अभिलेखों और बहियों से मिलात कर लिखा है और वे, जहां तक मैं/हम अभिनिश्चित करता हूँ/करते हैं, सही और पूर्ण हैं।

तारीख

विनिर्माता के हस्ताक्षर

[एक सं० 8(8)/83-ए ई आई(i)]

के० एम० बैं, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Heavy Industry)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 1984

S.O. 389(E).—The following draft of certain rules which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), is hereby published, as required by subsection (1) of that section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of sixty days from the date on which the Gazette containing the said notification is made available to the public.

Any objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft within the period so specified will be considered by the Central Government. Such objections or suggestions should be addressed to the Secretary, Ministry of Industry (Department of Heavy Industry), Udyog Bhawan, New Delhi : 110011.

DRAFT RULES

1. Short title.—These rules may be called the Automobile Cess Rules, 1984.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires—

- (a) 'Act' means the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951);
- (b) 'cess' means the cess levied and collected in terms of notification No. S.O. 932(E), dated 28-12-1983 of Department of Heavy Industry issued under sub-section (1) of section 9 of the Act;
- (c) 'Collector' means the Collector of Central Excise and includes the Additional Collector of Central Excise, the Deputy Collector of Central Excise, Assistant Collector of Central Excise and Superintendent of Central Excise;
- (d) 'Development Council' means the Development Council for Automobile and Allied Industries established under Section 6 of the Act;
- (e) 'Automobile' means motor cars, buses, trucks, jeep type vehicles, vans, scooters, motorcycles, mopeds and all other automobiles covered under the sub-heading (5) of the First Schedule to the Act;
- (f) words and expressions used herein and not defined but defined in the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) or the rules made thereunder, shall have the meanings respectively assigned to them in that Act or the rules.

3. Application of Central Excises and Salt Act and the rules made thereunder.—Save as otherwise provided in these rules, the provisions of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and the rules made thereunder including those relating to refund of duty, shall, so far as may, apply in relation to the levy and collection of the cess as they apply in relation to the levy and collection of the duty of excise on manufacture of automobiles under the Act and the rules.

4. Submission of returns.—(1) Every manufacturer shall submit to the Collector and to the Development Council on or before the 10th of every month a return in the Form specified in the Annexure to these rules of all stocks of items of automobiles manufactured or produced in, and removed from his undertaking during the previous month.

(2) If any manufacturer fails to furnish the return within the date specified in sub-rule (1) or furnishes a return which the Collector or the Development Council has reason to believe is incorrect or defective, the Collector may serve notice on the manufacturer calling upon him to produce all or any of his accounts relating to the automobiles manufactured or produced by him.

5. Proceeds of the cess.—The proceeds of the cess shall first be credited to the Consolidated Fund of India under the head '038—Union Excise Duties—Cess on Commodities Automobiles', and the Central Government may after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, hand over to the Development Council such sums as it may consider necessary from out of such proceeds after deducting therefrom the cost of collection.

6. Opening of Accounts.—The amount received by the Development Council under Rule 5 shall be kept in an account with the State Bank of India.

7. Accounts of the Development Council.—(1) The Development Council shall maintain proper accounts relating to the amount received by it under Rule 5.

(2) The audited statement of accounts for every financial year, together with the auditor's report thereon, shall be submitted to the Central Government.

8. Budget Estimates of the Development Council.—(1) The Development Council shall in each year prepare a budget for the ensuing financial year and submit the same for sanction to the Central Government on or before such date as may be specified by the Central Government.

(2) No expenditure shall be incurred until the budget is sanctioned by the Central Government.

(3) The budget shall be prepared in accordance with such instructions as may be issued from time to time by the Central Government.

9. Prescribed administrative expenses.—The Development council may utilise a sum, not exceeding 2 per cent of the amount received by it under Rule 5, to meet its expenses on account of office establishment and equipment, stationery, postage, telephones,

telegrams, telex, wages and allowances of staff employed in the secretariat, travel and daily allowance of members, and expenditure connected with heading of Council meetings.

ANNEXURE

(See Rule 5)

FORM OF MONTHLY RETURN TO BE SUBMITTED UNDER THE AUTOMOBILES CESS RULES, 1984

Month ending.....

Name of Factory.....

Address.....

Opening balance of goods subject to cess		Goods subject to Cess manufactured		Goods subject to cess removed	
Description	Quantity	Description	Quantity	Description	Quantity
1	2	3	4	5	6
Closing balance		Remarks			
Description	Quantity				
7	8	9			

I/We declare that I/We have compared the above shown particulars with the records and books of my/our factory and that they are in so far as I/We ascertain, accurate and complete.

Date.....

Signature of Manufacturer

[F. No. 8(8)/83-AEI(I)]
K. S. BAINS, Jt. Secy.